<u>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)</u>

सितंबर, 2019 माह का मासिक सारांश

<u>सितंबर, 2019 माह का महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:</u>

(क) "शिक्षुता पखवाड़ा" 30 सितंबर, 2019 को आरंभ किया गया था, जो 16 अक्तूबर, 2019 तक चला। पखवाड़े के भाग के रूप में उसी दिन "राज्य कौशल मंत्री राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता माननीय केंद्रीय मंत्री, एसडीई द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा एमएसडीई की यात्रा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र हेतु इसकी विभिन्न उपलब्धियां तथा पहलों पर चर्चा तथा उन्हें साझा करना था। एमएसडीई (2020 से 2025) के दृष्टि पत्र की व्याख्या करना, शिक्षुता संवर्धन के लिए "तृतीय पक्ष एग्रीगेटर" (टीपीए) सहायता हेतु प्रोत्साहन की घोषणा, 'कौशल का अधिकार' (आरटीएस) संबंधी दृष्टि पत्र तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनके शिक्षुता संबद्धता के प्रति वचनबद्धता सुनिश्चित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करना आदि शामिल था। सम्मेलन के दूसरे भाग में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया, जिसमें राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किए तथा एमएसडीई की विभिन्न कौशल विकास पहलों संबंधी सुझाव दिए। उपर्युक्त कार्यक्रम के दौरान एमएसडीई ने राज्यों, उद्योगों तथा शिक्षुओं के साथ मंत्रालय के सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षुता संख्या प्राप्त करने वाले राज्यों के साथ समझौता हस्ताक्षरित किए। 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्तमान वित्त-वर्ष के दौरान 2.6 लाख शिक्षुओं की वचनबद्धता के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। इसके अतिरिक्त, तृतीय पक्ष एग्रीगेटर (टीपीए) को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नई प्रायोगिक परियोजना भी 30 सितंबर, 2019 को आरंभ की गई थी।

(ख) संयुक्त सचिव (कौशल विकास), (एमएसडीई) की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) के सरकारी अधिकारियों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य कौशल विकास मिशन (जेकेएसएसडीएम) के साथ 16 सितंबर, 2019 को सिविल सचिवालय, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के सभी योग्य लाभार्थियों की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के तरीकों तथा इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। एनएसडीसी, डीजेएसएस तथा विभिन्न सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) सहित एमएसडीई के विभिन्न संगठनों के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हुए।

(ग) मुंबई में आईआईएस की स्थापना के लिए माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों,

अध्यक्ष, टाटा सन्स, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 11 सितंबर, 2019 को मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) की आधार शिला रखी।

(घ) सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) तथा सचिव, वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के बीच 13 सितंबर, 2019 को श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न बैठकों में हुई चर्चा के आधार पर कौशलीकरण स्कीमों के अभिसरण पर विचार-विमर्श किया गया। सचिव, एमएसडीई तथा सचिव, एमओएसपीआई के बीच एमएसडीई, एमओएसपीआई, एनएसडीए, एनएसडीसी तथा प्रबंधन और उद्यमशीलता एवं व्यावसायिक कौशल परिषद (एमईपीएससी) के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में उसी दिन एक अलग बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक की कार्य सूची मद विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से आंकड़ें एकत्रित करने का कार्य करने वाले कौशलीकरण गणनाकारों की समस्याओं की पहचान करना था। चर्चा के मुख्य क्षेत्रों में एमईपीएससी के अंतर्गत जॉब रोल का विकास, संपूर्ण कौशलीकरण पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन तथा सर्वेक्षणकर्ताओं का संग्रह तैयार करना, इन जॉब रोलों के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों का प्रमाणन आदि शामिल है।

(ड.) प्रशिक्षकों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देने तथा सराहना करने के लिए भावी तैयारी तथा कुशल जनशक्ति के सृजन की दिशा में उनके असाधारण योगदान के लिए विभिन्न सेक्टरों के 53 प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए 05 सितंबर, 2019 को कौशलाचार्य पुरस्कार 2019 का आयोजन किया गया था।

(च) मंत्रालय द्वारा जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) प्रबंधन बोर्ड के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है तथा माननीय मंत्री, एसडीई के अनुमोदन के साथ यह निर्णय लिया गया है कि जेएसएस बोर्ड में कम से कम 4 (चार) महिला सदस्य होंगी। इस संबंध में दिनांक 23.09.2019 को आदेश जारी कर दिया गया है।

(छ) संकल्प संबंधी एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन 3 और 4 सितंबर, 2019 को कोहिमा, नागालैंड में किया गया था। छह राज्यों नामत: नागालैंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, अरूणाचल प्रदेश तथा सिक्किम ने इस कार्यशाला में भाग लिया। क्षेत्रीय कार्यशाला के साथ-साथ जिला अधिकारियों तथा प्रशिक्षकों के साथ भी कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, संकल्प के अंतर्गत दिल्ली तथा महाराष्ट्र में भी एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके अलावा, एक प्रतिनिधिमंडल ने सिओल, कोरिया का दौरा किया, जिसका

आयोजन विश्व बैंक द्वारा किया गया था तथा राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) की स्थिति की समीक्षा करने तथा संकल्प के अंतर्गत राज्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई थी।

(ज) संशोधित पीएम-युवा स्कीम के कार्यान्वयन से पहले संशोधित पीएम-युवा के आधार पर प्रायोगिक परियोजना को मंत्रालय द्वारा 02.09.2019 को अनुमोदित किया गया है तथा सभी प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद इस परियोजना को 27 सितंबर, 2019 से कार्यान्वित किया जा सका।

(झ) 'औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव)' स्कीम के अंतर्गत प्रगति में कार्यक्रम में 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 84 आईटीआई की भागीदारी द्वारा त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर करना तथा अब तक कुल 157 आईटीआई ने निष्पादन आधारित अनुदान समझौते हस्ताक्षरित किए हैं; स्ट्राइव परियोजना के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित तथा अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कुल 29 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं; पीएफएमएस के अंतर्गत राज्य सोसायटियों के पंजीकरण, ईएटी मॉड्यूल का प्रशिक्षण तथा राजकोष से निधि अंतरण की सुविधा हेतु 12 राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसों का आयोजन शामिल है।

****